SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था

क्षमा चंद्राकर, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययन शाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

क्षमा चंद्राकर,

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययन शाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/06/2022
Revised on : -----
Accepted on : 29/06/2022
Plagiarism : 02% on 22/06/2022

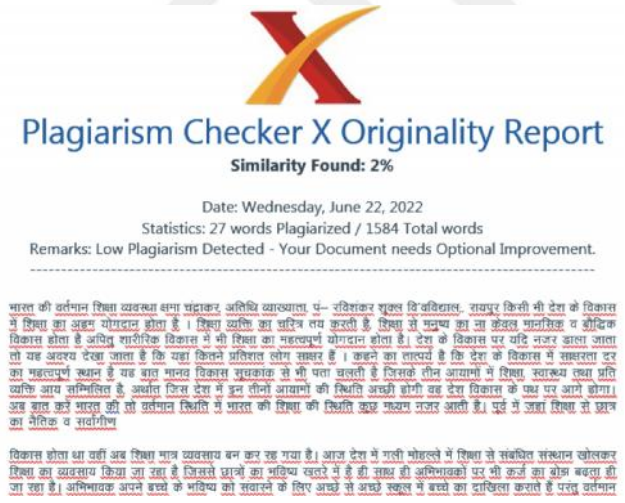

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

Date: Wednesday, June 22, 2022
Statistics: 27 words Plagiarized / 1584 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्षमा चंद्राकर, अतिथि व्याख्याता, पं- रविशंकर शुक्ल वि.विद्यालय, रायपुर किसी भी देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है । शिक्षा व्यक्ति का चरित्र तय करती है, शिक्षा से मनुष्य का ना केवल मानसिक व बौद्धिक विकास होता है अपितु शारीरिक विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के विकास पर यदि नजर डाला जाता तो यह अवश्य देखा जाता है कि यहां कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं । कहने का तात्पर्य है कि देश के विकास में साक्षरता दर का महत्वपूर्ण स्थान है यह बात मानव विकास सूचकांक से भी पता चलती है जिसके तीन आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है, अर्थात जिस देश में इन तीनों आयामों की स्थिति अच्छी होगी वह देश विकास के पथ पर आगे होगा। अब बात करें भारत की तो वर्तमान स्थिति में भारत की शिक्षा की स्थिति कुछ मध्यम नजर आती है। पूर्व में जहां शिक्षा से छात्र का नैतिक व सर्वांगीण

विकास होता था वहीं अब शिक्षा मात्र व्यवसाय बन कर रह गया है। आज देश में गली मोहल्ले में शिक्षा से संबंधित संस्थान खोलकर शिक्षा का व्यवसाय किया जा रहा है जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है ही साथ ही अभिभावकों पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराते हैं परंतु वर्तमान

शोध सार

आधुनिक युग में नई–नई तकनीकों का प्रयोग सर्वत्र देखने को मिलता है। वर्तमान में शिक्षा जगत में भी अनेक तरह की प्रविधियां व उपकरणों का प्रयोग हो रहा है जिससे हमारी शिक्षा को नया आयाम मिल सके। हाल ही में इसका उपयोग कोविड–19 महामारी के समय ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में देखने को मिला, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद भी पढ़ाई में निरंतरता बनी रही। भारत में लंबे समय से शिक्षा प्रणाली में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया गया था, परंतु नई शिक्षा नीति 2020 से आशा की किरण दिखाई दे रही है जिसमें शिक्षा के माध्यम में मातृभाषा को स्थान दिया जा रहा है। नीति में अनेक अनछुए पहलुओं को रखा गया है जो निश्चित ही देश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देगा। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों ने भी देश में लूट मचा रखी है, आवश्यकता है कि इन पर भी लगाम लगाया जाए। भारतीय संस्कृति के साथ–साथ शिक्षा में नैतिक शिक्षा को भी उचित स्थान दिया जाए। आजकल के छात्रों में नैतिकता कम ही दिखाई देता है नैतिकता के अभाव में व्यक्ति, परिवार व समाज का पतन हो जाएगा। अतः माता–पिता के साथ–साथ शिक्षण संस्थानों द्वारा भी नैतिक शिक्षा दी जाए जिससे देश का विकास हो सके।

मुख्य शब्द

नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन एजुकेशन, क्षेत्रीय भाषा, नैतिक शिक्षा, सर्वांगीण विकास.

किसी भी देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। शिक्षा व्यक्ति का चरित्र तय करती है, शिक्षा से मनुष्य का ना केवल मानसिक व बौद्धिक विकास होता है अपितु शारीरिक विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के विकास पर यदि

नजर डाला जाता तो यह अवश्य देखा जाता है कि यहां कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। कहने का तात्पर्य है कि देश के विकास में साक्षरता दर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात मानव विकास सूचकांक से भी पता चलती है जिसके तीन आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है, अर्थात् जिस देश में इन तीनों आयामों की स्थिति अच्छी होगी वह देश विकास के पथ पर आगे होगा। अब बात करें भारत की तो वर्तमान स्थिति में भारत की शिक्षा की स्थिति कुछ मध्यम नजर आती है। पूर्व में जहां शिक्षा से छात्र का नैतिक व सर्वांगीण विकास होता था वहीं अब शिक्षा मात्र व्यवसाय बन कर रह गया है। आज देश में गली मोहल्ले में शिक्षा से संबंधित संस्थान खोलकर शिक्षा का व्यवसाय किया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है ही साथ ही अभिभावकों पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराते हैं। पहले के समय में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी जहां छात्र गुरु दक्षिणा देकर शिक्षार्जन किया करता था, वहीं अब मोटी फीस के लिए पढ़ाई, खेलकूद, अन्य गतिविधियों का हवाला देकर पैसे लूटे जाते हैं। शिक्षण संस्थान ऐसा होना चाहिए जिससे एक छात्र का सर्वांगीण विकास हो तथा वह समाज व देश में अपना योगदान दे सकें। जॉन लॉक ने भी कहा है ''जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है, वैसा ही मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है।''

सकारात्मक पहलू की बात करें तो हाल ही में भारत में जो परिस्थितियों परिस्थितियां कोविड–19 के कारण उत्पन्न हुई उसमें शिक्षा व्यवस्था को अनेक हानियां हुई फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट व अन्य शिक्षण सामग्री घर बैठे उपलब्ध हो जाने के कारण शिक्षा की स्थिति को बदहाल होने से रोका जा सका। जहां एक ओर ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट तो जरूर आई वहीं दूसरी ओर स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान के बंद होने के बावजूद भी छात्रों को अधिक हानि नहीं उठानी पड़ी। भारत सरकार व राज्य सरकार के प्रयासों के ही चलते छात्रों को पढ़ाई से वंचित होने से बचाया जा सका। ऑनलाइन शिक्षा के भी दो पहलू देखने को मिले, जहां कुछ छात्रों ने इसका लाभ शिक्षा को निरंतर रखने में उठाया तो वहीं कुछ छात्रों का आधार कमजोर हो गया, जिससे तकनीकी कारण, अकुशल शिक्षक व शिक्षक –छात्र अंर्तक्रिया में कमी हो जाने के कारण कमजोर छात्र और अधिक कमजोर हो गए। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में स्थिति जहां ठीक रही वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को तकनीकी ज्ञान में कमी व अशिक्षित अभिभावक व दुर्गम स्थानों में नेटवर्क आदि के कारण अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा।

कोविड–19 के बीच ही भारत में शिक्षा में बहुत बड़ा कार्य भी हुआ, नई शिक्षा नीति 2020 जिसका का खॉका 2019 में तैयार हो गया था जिसे 2020 में व्यापक तौर पर लागू करने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सन् 1948 में डॉ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। तब से लेकर अब तक कई आयोग समय–समय पर बनाए गए। इसी कड़ी में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के– कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित नई शिक्षा नीति बनाई गई। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, इसके बाद उसे 1986 में संशोधन किया गया। तदुपरांत 1992 में भी कुछ संशोधन किए गए जिसके बाद 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया जिस पर सार्वजनिक परामर्श हुए इस नीति में संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया देते हुए 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली लागू करने की बात की गई।

नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुः

- प्राथमिक शिक्षा में 3 से 8 वर्ष को दो भागों में बांटा गया हैः
  3–6 वर्ष – आंगनबाड़ी /बालवाटिका/पूर्व स्कूल
  6–8 वर्ष– प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 व 2
- भाषाई विविधता का संरक्षण करते हुए पांचवी कक्षा की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा

को माध्यम बनाने पर बल दिया गया है।

- शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कक्षा– 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया गया जाएगा तथा इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में भी बदलाव किए जाएंगे।
- शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार कार्य किया जाएगा जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावी और पारदर्शी होगी तथा उनका समय–समय पर कार्य–प्रदर्शन आँकलन के आधार पर पदोन्नति किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26–3 प्रतिशत वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एम. फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

भारत के शिक्षा प्रणाली के इतिहास में निश्चित ही यह ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है क्योंकि लंबे समय से शिक्षा प्रणाली में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। नई शिक्षा नीति शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता आदि पर केंद्रित है जो निश्चित ही शिक्षा प्रणाली के आधारभूत कमियों को दूर करने का कार्य कर सकता है।

वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की नीति के अलावा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ने भी अपनी भूमिका अदा की है। शिक्षा के अधिकार ने क्रांति ला दी। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, बेटी बचाओ –बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर सभी को समान शिक्षा की उपलब्धता पर केंद्रित है। उच्च शिक्षा में उपलब्ध छात्रवृत्ति ने भी छात्रों के मनोबल को ऊंचा उठाया है। छात्रावास तथा छात्रवृत्ति ने दूरस्थ इलाकों में रहने वाले छात्रों को की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की राह आसान कर दी। भारत में अनुसंधान कार्य भी छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं। अनुसंधान में गुणवत्ता लाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग अनवरत् प्रयास कर रहा है। नई युवा पीढ़ी की सोच तथा शोध निश्चित रूप से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकती है।

भारतीय युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ''मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।'' किसी भी देश की ताकत उसमें रहने वाले युवा ही है और शिक्षा द्वारा युवाओं को उचित दिशा मिल जाती है। शिक्षा मनुष्य में गुणों को समाहित कर अवगुणों को दूर करता है। वर्तमान में आज के युवाओं में नैतिकता का अभाव देखा जाता है जिसकी कमी शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षक के रूप में बच्चे घर पर माता–पिता द्वारा सद्चरित्र आचरण सीखते हैं तथा यही कार्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षक एक छात्र को सही मार्गदर्शन देकर समाज का आदर्श चरित्र बना सकता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी माता–पिता, गुरुजनों आदि का सम्मान करना भूलता जा रहा है, जिसे नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में गुरू को देव तुल्य माना जाता है। वास्तव में गुरु व शिक्षा ही एक मनुष्य का चरित्र तय करती है। मनुष्य को यदि अच्छे गुरु का साथ मिल जाता है तो वह मूल्यवान बन जाता है, परंतु आज शिक्षा जगत में गुरु–शिष्य की स्थिति वैसी नहीं रह गई है। जहां शिक्षक धैर्य की जगह क्रूरता से कार्य लेने लगे तो शिष्य वही भी देवतुल्य गुरु का अपमान करने लगे है। शिक्षा जो मनुष्य का भविष्य तय करती है उसे सिर्फ बौद्धिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जाता जाना चाहिए, अपितु संपूर्ण विकास पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्तर पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जहां शिक्षण संस्थान छात्र को अपने फायदे के लिए प्रवेश देते हैं परंतु छात्रों को शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का आधा फायदा भी नहीं पहुंचा पाते। वास्तविकता में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र में सीखने की व जानने की इच्छा दिखाई दे, वह नित नये–नये प्रयोग करें और वास्तविक जगत को समझने का प्रयास अपने दम पर करें। शिक्षा में सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, अपितु छात्र के तार्किक ज्ञान में वृद्धि कर स्वयं सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। वर्तमान

में शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अनेक विधियों व उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा प्रणाली में सिर्फ स्कूल–कॉलेज के छात्रों तक ही नहीं प्रौढ़ शिक्षा को भी आसान कर दिया है, विशेषकर ऑनलाइन एजुकेशन, मुक्त विश्वविद्यालय आदि ने सीखने व पढ़ने वाले लोगों की राह आसान कर दी है।

निष्कर्ष

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जहां कुछ खामियां हैं तो वहीं नई तकनीकों, आसान उपलब्धता स्कूल–कॉलेजों की संख्या में वृद्धि ने शिक्षा प्राप्त करना आसान बना दिया है। आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थान शिक्षा को व्यवसाय ना बनाकर जिम्मेदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभायें, तथा सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक करके देश को विकासशील से विकसित बनाने में अहम भूमिका निभायें। देश में बालक–बालिका को एक समान शिक्षा देकर साक्षरता दर के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल सौरभ कुमार, *भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास,* साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा,।
2. पांडेय सुधांशु कुमार, (2020) *शिक्षा नीति,* नोशन प्रेस पब्लिकेशन, चेन्नई, 18 मार्च 2021।
3. www.education.gov.in
4. www.indiaeducation.net

****